



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक 1367 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, फरवरी, 06-02-2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, for renewal of FC Approval collection of Minor Minerals from Sharda River in Haldwani Forest Divisions, District Champawat (Uttarakhand).

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8-61/1999-FC(Pt.VII) Dated: 31 st January, 2023.

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा आपत्तियाँ लगायी गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय की पत्र संख्या 1334/12-1 दिनांक 02.02.2023 से आपत्तियों का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 2035/12-1 दिनांक 06.02.2023 से पुनः संशोधित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

आपत्ति	प्रतिउत्तर
i. The State Govt. has now submitted the mining plan approved by the Department of Mining and Geology Govt. of Uttarakhand. The said mining plan approved for next 5 years contains a letter No. 2169/VII-A-1/2021- 19(ख)2013 dated 23.12.2021 issued by the Government of Uttarkhand wherein the condition no. 13 stipulates that the User Agency will carry out mining after leaving 15% area on each bank of the river. Whereas, the condition at Sr no (xi) of the approval dated 23.01.2013 stipulates that extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of the river bed after leaving intact one fourth of the width of the river bed along its each bank. The said condition which is contrary to the conditions of stage-II approval needs attention of the State government and clarification may accordingly be submitted	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून के शासनादेश संख्या- 133/VII-A-1 /2023/ 19-ख / 2013 दिनांक-30 जनवरी 2023 के द्वारा शासनादेश 2169/VII-A-1/2021-19-ख/ 2013 दिनांक-23 दिसम्बर 2021 की शर्त/प्रतिबंध संख्या-13 में अंकित 15% स्थान रिक्त छोड़ने को संशोधित कर 25% कर दिया गया है। शासनादेश की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
ii. The State Govt. has confirmed that they have carried out CA in the areas namely Sharda Tapu 35 & 38 (25 ha), Sharda Tapu 37 (63 ha), Sharda Tapu 42 (16 ha) and Sharda Tapu 42 (20 ha) (total 124 ha) in safety zone which is part of the area proposed for diversion. The Compensatory Afforestation is required to be carried out in lieu of diversion of forest land and carrying out of CA over the same diverted forest land is not tenable. The reasons and justification for the same be submitted by the State.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि शारदा टापू कक्ष संख्या-42 में वर्ष 2016-17 में 16 हे० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य किया गया था, जिसका कुछ भाग प्रस्ताव के डाउन स्ट्रीम लैफ्ट सेफ्टी जोन के अन्तर्गत स्थित है। क्षेत्र रिक्त होने के कारण वृक्षारोपण कार्य किया गया था। अतः सेफ्टी जोन में किये गये वृक्षारोपण 12.50 हे० के सापेक्ष पृथक से शारदा रेंज के अन्तर्गत ब्रह्मदेव ब्लाक कक्ष संख्या ए-2 में 12.50 हे० का चयन कर लिया गया है, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। चयन किये गये क्षेत्र की के.एम.एल. फाइल प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

आपत्ति	प्रतिउत्तर
iii. All the parameters prescribed in the Handbook of guidelines dated 28.03.2019 have still not been included in the cost benefit analysis, which is required to be done.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईड लाईन दि. 28.03.2019 से अनुसार cost benefit analysis संशोधित कर दिया गया है, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
4. The State Government shall however immediately submit the reply to the observations as contained above in Para 2 of the letter along with the latest point wise status of compliance of the conditions stipulated in the S-II approval dated 11.02.2013 so that the proposal for renewal of validity of forest clearance can be placed before the FAC for consideration.	अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नक सहित सादर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1367 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 2035/12-1 दिनांक 06.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 2035/12-1 हल्द्वानी,

दिनांक 06/02/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, for renewal of FC Approval collection of Minor Minerals from Sharda River in Haldwani Forest Divisions, District Champawat (Uttarakhand).

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8-61/1999-FC(Pt.VII) Dated: 31 st January, 2023.

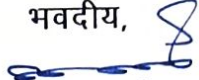
महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा आपत्तियों लगायी गयी थी, जिसके कम में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है-

आपत्ति	प्रतिउत्तर
i. The State Govt. has now submitted the mining plan approved by the Department of Mining and Geology Govt. of Uttarakhand. The said mining plan approved for next 5 years contains a letter No. 2169/VII-A-I/2021- 19(ख)2013 dated 23.12.2021 issued by the Government of Uttarkhand wherein the condition no. 13 stipulates that the User Agency will carry out mining after leaving 15% area on each bank of the river. Whereas, the condition at Sr no (xi) of the approval dated 23.01.2013 stipulates that extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of the river bed after leaving intact one fourth of the width of the river bed along its each bank. The said condition which is contrary to the conditions of stage-II approval needs attention of the State government and clarification may accordingly be submitted	उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून के शासनादेश संख्या- 133/VII-A-1/2023/19-ख / 2013 दिनांक-30 जनवरी 2023 के द्वारा शासनादेश 2169/VII-A-1/2021-19-ख/ 2013 दिनांक-23 दिसम्बर 2021 की शर्त/प्रतिबंध संख्या-13 में अंकित 15% स्थान रिक्त छोड़ने को संशोधित कर 25% कर दिया गया है। शासनादेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
ii. The State Govt. has confirmed that they have carried out CA in the areas namely Sharda Tapu 35 & 38 (25 ha), Sharda Tapu 37 (63 ha), Sharda Tapu 42 (16 ha) and Sharda Tapu 42 (20 ha) (total 124 ha) in safety zone which is part of the area proposed for diversion. The Compensatory Afforestation is required to be carried out in lieu of diversion of forest land and carrying out of CA over the same diverted forest land is not tenable. The reasons and justification for the same be submitted by the State.	शारदा टापू कक्ष संख्या-42 में वर्ष 2016-17 में 16 हे० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य किया गया था, जिसका कुछ भाग प्रस्ताव के डाउन स्ट्रीम लैफ्ट सेप्टी जोन के अन्तर्गत स्थित है। क्षेत्र रिक्त होने के कारण वृक्षारोपण कार्य किया गया था। प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल की जाँच करने पर मात्र 12.5 है० क्षेत्र सेप्टी जोन में पाया गया, जिसके सापेक्ष पृथक से शारदा रेंज के क्षेत्रान्तर्गत ब्रह्मदेव ब्लाक कक्ष संख्या-ए 2 क्षेत्रफल 12.5 हे० का चयन कर लिया गया है जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। चयन किये गये क्षेत्र की के.एम.एल. फाइल पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-2)

आपत्ति	प्रतिउत्तर
iii. All the parameters prescribed in the Handbook of guidelines dated 28.03.2019 have still not been included in the cost benefit analysis, which is required to be done.	गाईड लाईन दि. 28.03.2019 से अनुसार cost benefit analysis संशोधित कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
4. The State Government shall however immediately submit the reply to the observations as contained above in Para 2 of the letter along with the latest point wise status of compliance of the conditions stipulated in the S-II approval dated 11.02.2013 so that the proposal for renewal of validity of forest clearance can be placed before the FAC for consideration.	अनुपालन आख्या संलग्न है। (संलग्नक-4)

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय, 
(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

चम्पावत।

देहरादून, दिनांक 30 जनवरी, 2023

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

विषय: उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद चम्पावत के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली शारदा नदी में 384.69 है० आरक्षित वन क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2169/VII-A-1/2021-19-ख/2013, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 की शर्त/प्रतिबन्ध संख्या-13 में टंकण त्रुटिवश 25% के स्थान पर 15% अंकित हो गया है, जिसे 15% के स्थान पर 25% के रूप में संशोधित किया जाता है, तदनुसार भविष्य में इसे 15% के स्थान पर 25% पढा और समझा जाय।

संगत शासनादेश दिनांक 23.12.2021 में किया गया संशोधन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्त/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या- /VII-A-1/2023/19-ख/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दिरा नगर, फोरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

Table-A: Casess under which a cost-benefit analysis for forest diversion are required (SHARDA RIVER).

Sr. No	Nature of proposal	Applicable/ Not Applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land upto 20 hectares in plains and upto 5 hectares in hills.	N/A	These proposals are to be considered on case by case basis and value of judgment.
2	Proposal for defence installation purposes and soil prospecting (prospecting only)	N/A	In view of National Priority accorded to these sectors, the proposals would be critically assessed to help ascertain that the utmost minimum forest land in diverted for non-forest use.
3	Habitation, establishment of industrial unit, tourist lodges/complex and other building construction.	N/A	These activities being detrimental to protection and conservation of forest. As a matter of policy, such proposals would be rarely entertained.
4	All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, Minor, Medium and Major irrigation Projects, hydel projects mining activity, railway lines, location specific installations like micro-wave stations, auto repeater centres, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost-benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non-forest use is in the overall public interest.


 Divisional Manager, (Mining)
 Utrakhand Forest Development Corporation,
 Khanan Sharda Division (Champawat)

Cost of Project:-

Name of project: – Collection of the minor mineral from the SHARDA RIVER, Utrakhnad forest Development Corporation, TANAKPUR (Champawat)

Sr.No	Particulars	Approx Amount (in lakhs)	Remark
1	Total cost (Investment incurred) for 10 years	2110.00	
(A)	*Construction Cost of the Project	2110.00	Fencing of Safety zone, Staff Salary, infrastructure Labour welfare, Repair and maintenance, Other expenditures. Already included above.
(B)	N.P.V Amount to be deposited@--- lakh/Ha	N/A	N/A
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	N/A	N/A
Total (A+B+C)=		2110.00	
2	Benefits:- Benefits from taking age of Project as 10 Years	6355.76	
(A)	Economic Benefits-Market Development Taking	2110.00	Production Cost and other
(B)	Economic benefits due to of direct & indirect employment due to the project.	3245.76	About 2254 labours will be working for 240 day/year for 10 years @Rs 600=3245.76 Lakh. These Labours are directly paid by buyer.
©	Employment Generation Due to other activities	1000.00	Truck Owner + Machine Worker for Ten Years
(D)	Therefore construction of Economically viable and social beneficial.	-	
Total (A+B+C+D)=		6355.76	

* For calculating the total cost of 10 years average cost of investment for last 3 years was multiplied with 10 and obtained value was divided by the total mining area of both the rivers i.e Sharada to reach to per ha. Investment cost finally for the calculation of total cost of Sharda River, the mining area of sharada i.e. 384.69 hact was multiplied with per hact cost.

Note:- Total expenditure SI No 1=Rs 2110 (In Lakhs)

Benefit SI No 2=Rs 6355.76 (In Lakhs)

Therefore, Benefits/cost Ratio=6355.76 /2110=3.01

Therefore the project is economically viable socially beneficial.


Divisional Manager, (Mining)
Utrakhnad Forest Development Corporation,
Khanan Sharda Division (Champawat)

Table-B: Estimation of cost of forest diversion (KOSI RIVER).

Sr. No	PARAMETERS	REMARKS
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion.	Not Applicable as per as Supreme Court order of 28 March 2008
2	Loss of animal husbandry productivity including loss of fodder.	Considering the river bed as open forest of Ecoclass iv. The 10% of NPV value would be approximately 02 Crore 57 lakh 79 Thousand and 615 Rupees. (670140*384.69*0.1 = 25779615)
3	Cost of human resettlement.	There is no resettlement as the area is a reserved forest within river bed.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Road, Building, Schools, Dispensaries, Electric line, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	No public facilities exist in the proposed site and there is no need for diversion of infrastructure in and around the site.
5	Possession value of forest land diverted.	Considering the river bed as open forest of Ecoclass iv. The 30% of NPV value would be approximately 07 Crore 73 lakh 38 Thousand and 846 Rupees. (670140*384.69*0.3 = 77338846)
6	Cost of Suffering to oustees.	Not Applicable. The area is reserved forest within river bed and no rehabilitation of oustees is needed
7	Habitat Fragmentation Cost	Considering the river bed as open forest of Ecoclass iv. The 50% of NPV value would be approximately 12 Crore 88 lakh 98 Thousand and 078 Rupees. (670140*384.69*0.5 = 128898078)
8	Compensatory Afforestation and soil & moisture conservation cost.	The Compensatory Afforestation is not applicable the cost of CA already has been deposited in the past.

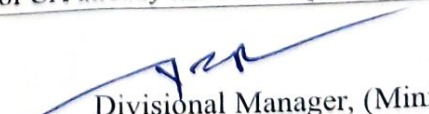

Divisional Manager, (Mining)
Uttarakhand Forest Development Corporation,
Khanan Sharda Division (Champawat)

Table-C- Existing guidelines for astimating benefits of forest-diversion in CBA (KOSI RIVER).

Sr. No	PARAMETERS	REMARKS
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	NA
2	Benefits to economy due to the incremental economic benefit in monetary the specific project.	As given in cost benefit ratio chart, the total expenditure is Rs 2110 Lakhs and the benefit will be Rs 6355.76 lakh which can be more.
3	No. of population benefited.	Approximately 2254 labourers are directly benefitted
4	Economic benefited due to of direct and indirect employment due to the project	Along with labourers, more 1000 truck owners and drivers, shop keepers etc get benefited.
5	Economic benefited due to Compensatory Afforestation.	The Compensatory Afforestation is not applicable as the CA is already done in the past. (it's a renewal case)


Divisional Manager, (Mining)
Uttrakhand Forest Development Corporation,
Khanan Sharda Division (Champawat)

Scanned by 4

3

**Govt. of India Ministry of Environment & Forests (FC Division) , New
Delhi Leter No- F.No-8-61/1999 FC(pt iii), Dated-11rd February, 2013**

Compliance of Forest Clearance Sharda River

(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	It is being complied with user agency
(ii)	Compensatory afforestation over the degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department from funds realised from the User Agency.	It is being raised and maintained by the Uttarakhand Forest Department.
(iii)	All the funds received from user Agency under the project shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the saving bank account of the concerned state CAMPA in the corporation bank, CGO complex, Lodhi Road , New Delhi.	Being complied by forest department.
(iv)	No collection of minor minerals shall be Permitted form the portion of the Sharda river located on upstream of the Sharda barrage.	Being complied by forest department.
(v)	To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall for formulated a transparent and unbiased procedure for engagement of labours for extraction of the minor minerals form the forest land proposed for diversion.	labours are not directly engaged by User agency Those engaged by transporter. Though provision of supply of fuel wood in winter season, organize muskan center medical camp, safe drinking water as per F.C. norms
(vi)	The collection of minor minerals after 31 st Day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate form the monitoring committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests Uttarakhand constituted vide Government of Uttarakhand's letter number <u>14-1/x-3-13-08(14)/2018-T.C.</u> dated 29.01.2013 to the effected that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instruction issued by monitoring committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;	The State Government vide letter no. <u>14-1/x-3-13-08(14)/2018-T.C.</u> dated 29.01.2013 has constituted a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand to review annually the status of compliance of the stipulated conditions.

(vii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with proposed pawalgarh conservation reserve the state govt may explore feasibility to relocate the settlements form the sunderkhal village by using state CAMPA funds.

The exercise is being done by state forest department and state government

(viii) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special Purpose Vehicle (SPV) constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand vide order number 383/X-3-12-8(14)/2009 dated 30th may 2012. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals;

Funds are being transferred to the Forest Department vide letter no.383/X-3-12-8(14)/2009 dated 30th may 2012. as per rules.

विगत 10 वर्षों के दौरान वन विभाग को शारदा नदी से कार्बोसिलिका के रूप से प्राप्त शरदा नदी के मुहाने का वित्तीय वर्षवार विवरण

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	कार्बोसिलिका मूल्य	
		कार्बोसिलिका मूल्य में प्राप्त धनराशि	ताम्र का 50 प्रतिशत कम से वन विभाग को मुहाने की मूल्य धनराशि
1	2012-13	520,890.00	260,445.00
2	2013-14	3,605,600.00	1,802,800.00
3	2014-15	2,812,250.00	1,406,125.00
4	2015-16	3,144,773.00	1,572,386.50
5	2016-17	4,994,007.00	2,497,003.50
6	2017-18	7,753,299.00	3,876,649.50
7	2018-19	7,767,538.00	3,883,769.00
8	2019-20	5,011,356.00	2,505,678.00
9	2020-21	5,622,641.00	2,811,320.50
10	2021-22	5,272,818.00	2,636,409.00
		46,534,672.00	23,267,339.00

(ix) The State Government shall through the Central soil and water Conservation Research & Training Institute (CSWCRTI) Dehradun assess the quantity minor minerals that may sustainably be collected form the said portion of the Sharda river intimate the same to the Ministry of Environment & Forests;

The condition is being complied with.

(x) The quantity of minor mineral collected during a working season shall not be more than the sustainable quantity as assessed by the CSWCRTI, Dehradun;

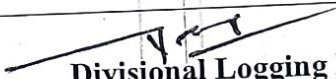
The condition is being complied with by the Utrkhand state forest corporation the year wise details of the extraction of minor minerals is as follows:-

S.No.	Year	Extraction
-------	------	------------

			(Cub. meter.)
	1	2012-13	215,611.2237
	2	2013-14	321,757.5471
	3	2014-15	286,349.0125
	4	2015-16	244,749.0227
	5	2016-17	341,286.2923
	6	2017-18	568,551.9300
	7	2018-19	398,870.7400
	8	2019-20	292,798.3500
	9	2020-21	419,324.1600
	10	2021-22	225,834.9700
	11	2022-23 (till 23 rd Jan. 2023)	-
(xi)	Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact the one-fourth of width of the river bed along its each bank;		The extraction of minor minerals is restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one-fourth of width of the river bed along its each bank.
(xii)	To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 m and it shall gradually reduced till it reaches boundary of the permissible zone.		The collection of minerals is carried out as per this para. The maximum permissible depth never exceeds 3m. in the centre of the river bed. being complied by forest department
(xiii)	To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, State Forest Department shall set up adequate number of check post during the collection season.		The condition is being complied with the help of Forest Department. The user agency has established 02 gates for Trucks/Dumper gates to regulate and maintain the record of the quantity collected during the season. To check illegal mining, the Electronic weighbridges are under online CCTV Camera & all the vehicles transporting material are checked by RFID on each gate. Apart from this, Haldwani forest

	division, haldwani has constituted van suraksha dal while user agency has also constituted Gasti dal to check illegal mining.
(xiv) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1 st October to 31 st May of the subsequent year.	The condition is being complied every year.
(xv) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.	The condition is being complied with. Minor minerals are collected manually by using hand tools. Further explosive and heavy machineries is not used for breaking /collection of minor minerals.
(xvi) Collection time shall be from sun-rise to sun-set.	The conditions is complied every year.The gate are shutdown after sun-set. The forest department monitors the timing on daily bases
(xvii) No labour camp shall be setup in the forest area for the labourers egnaged in collection of the minor mineral.	No labour camp was setup in the forest area for the labourers engaged in the collection of the minor mineral.
(xviii) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries.	The condition is being complied with. The forest department monitors it periodically
(xix) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests.	The user agency provides firewood to the laboures in the mining season Drinking water is being provided medical camp are organized.
(xx) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced	Being complied by forest deapartment

	cement concrete pillars, each inscribed with its serial number DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoin pillars etc.	
(xxi)	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal.	The condition is being complied with. The area is being used for the purpose as specified in the proposal.
(xxii)	User agency shall submit annual self – monitoring report, indication status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.	The monitoring report is being prepared and submitted to the state government and regional office.
(xxiii)	Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and	The condition is being complied with.
(xxiv)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	The compliance of the provision of the acts, rules, regulations, guidelines as applicable to the project is being ensured.


Divisional Logging Manager
 Uttarakhand Van Vikas Nigam
 Khanan Sharda Tanakpur